राष्ट्रीय सनातन पार्टी का नीतिगत घोषणापत्र

राष्ट्रीय सनातन पार्टी सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष !

हम एक उज्ज्वल, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध और संस्कारवान भारत के लिए और अपनी सनातन सभ्यता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं जिस पर हर तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। हम भारत के सनातन समाज की आवाज हैं। हमसे जुड़ें और सहयोग करें।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी

सनातन धर्म को संवैधानिक संरक्षण दिलाने के लिए कार्यरत एकमात्र राजनैतिक पार्टी

राष्ट्रीय सनातन पार्टी भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत एकमात्र ऐसी राजनैतिक पार्टी हैं जोकि सनातन धर्म को संवैधानिक संरक्षण दिलाकर भारत को संसार का सबसे शक्तिशाली व सम्पन्न राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री विश्वजीत सिंह अनंत जी राष्ट्रीय सनातन पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी का ध्येय वाक्य है “ राष्ट्रहित सर्वोपरि”। इसका अभिप्राय है कि हमारी पार्टी और भावी सरकार जो भी निर्णय लेगी वे व्यक्ति, समाज, मत, पंथ, सम्प्रदाय, जाति, क्षेत्र आदि के हितों से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र हित में किये जायेंगे।

सभी निर्णय समानता के सिद्धान्त पर किये जायेंगे। ईसाईंयों, बौद्धों व मुस्लिमों के मत/मजहब के समान सनातन धर्म को रिलीजन/मत की मान्यता देकर संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जायेगा।

हम सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सुधारों को प्राथमिकता देगे। चुनाव शुद्धिकरण (**Electroral Reform**) करके राजनेताओं द्वारा चुनाव में किए गए वादे**,** चाहे वे घोषणा पत्र के रूप में हों अथवा मंच पर जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए गए हों, उन्हें एक कानूनी अभिलेख (**Legal Documents**) बनाया जाएगा।

स्त्री सशक्तिकरण के लिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढाई जाएगीं। बच्चों को प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य व नि:शुल्क दी जाएगी। इतिहास व पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन कराया जाएगा। मूल्यों पर आधारित संस्कारों के साथ भारतीय भाषाओं में सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनायी जायेगी।

विज्ञान, गणित, तकनीकी, प्रबंधन, अभियन्त्रिकी, चिकित्सा व प्रशासकीय आदि सभी प्रकार की शिक्षा राष्ट्रभाषा, संस्कृत भाषा व अन्य प्रादेशिक मातृभाषाओं में ही दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विद्यालयों में चरित्र निर्माण शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा व सैन्य शिक्षा अनिवार्य की जायेगी।

देश के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएगी। आयुर्वेद, योग, पंचगव्य, प्राकृतिक, सिद्ध व यूनानी आदि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर अनुसन्धान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित किया जाएगा।

भारत में चल रहे ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के समस्त कानूनों को बदला जायेगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक सौ रूपये से अधिक बड़े नोटों का प्रचलन बंद किया जाएगा। बलात्कार, दहेज हत्या, गौहत्या, आतंकवाद व मिलावट करने वालों के विरूद्ध मृत्युदण्ड का कानून बनाकर समस्त भारतीयों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

देश में फास्टट्रेक कोर्ट बनवाकर एक से तीन माह में तुरन्त न्याय की व्यवस्था की जाएगी। कोर्ट में जूरी व्यवस्था को लागू किया जायेगा। एक देश – एक कानून बनाया जायेगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, अर्थ व कृषि व्यवस्थाओं का पूर्ण भारतीयकरण व स्वदेशीकरण किया जाएगा।

स्वदेशी अर्थ व्यवस्था की ऐसी नीतियाँ बनायी जाएगी जिससे रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न हो तथा रुपये का अवमूल्यन रुके, रूपये को डालर व पौंड के बराबर लाया जा सकें, जो लगभग 15 अगस्त 1947 के समय में था।

लघू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा तथा चीन की तरह ही अपने देश के युवाओं को व्यापार करने के लिए एकल खिड़की तंत्र प्रणाली (**One Window system Develop**) विकसित करेगे ताकि लोगों को व्यापार करने के लिए आवश्यक पूँजी और संसाधन सरलता से उपलब्ध हो सकें।

किसान आयोग का पुनर्गठन करके कृषि के औद्योगीकरण, खाद्य–प्रसंस्करण व फसलों के मूल्यांकन की एक स्वस्थ व नई नीति बनायी जाएगी, जिससे खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सके, गाँवों से पलायन रूके,

साथ ही किसान आत्महत्या के लिए मजबूर न हो। तथा किसानों को उनकी लागत का कम से कम दो गुना मूल्य मिल सके।

देश के छात्र-छात्राओं को सैन्य शिक्षा दिया जाना अनिवार्य करेगे, जिससे सैनिकों की कमी नहीं रहेगी। सेना में अग्निवीरों को स्थाई नियुक्ति दी जायेगी। सैनिक और अर्धसैनिक बलों, तथा पुलिस के जवानों को अत्याधुनिक शस्त्र और ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि हमारी सेना और हमारे जवान हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम हों। सेना सहित सभी शासकीय सेवाओं में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जायेगा।

सभी सार्वजनिक सेवाओं, सारे विभाग, तथा पूरी सार्वजनिक प्रणाली का उपयोग आम जनता के उत्थान के लिए किया जाए। सभी नागरिकों को भूमि, जल, जंगल पर अधिकार मिले, सड़क, पानी और बिजली की आपूर्ति, संचार, परिवहन, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आवास, शिक्षा और चिकित्सा जैसी उचित व अनिवार्य सुविधाएं सरलता से मिल सकें।

कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, पर्यावरण तथा सैन्य क्षेत्र सभी में एक सशक्त समन्वय हो ताकि किसी का अहित किए बिना सभी क्षेत्रों में उन्नति हो सके। सभी नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों की पूरी जानकारी हो तथा वे अपनी क्षमताओं का उपयोग राष्ट्र निर्माण में कर सकें।

संक्षेप में हम राष्ट्रीय सनातन पार्टी के द्वारा इस देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं का परिवर्तन करके बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, अशिक्षा व असुरक्षा से मुक्त स्वस्थ, समृद्ध, शक्तिशाली एवं संस्कारवान भारत का पुनर्निर्माण करेगे।

वर्तमान व्यवस्था भ्रष्ट है परन्तु इसमें राष्ट्रभक्त, ईमानदार व चरित्रवान लोग भी है, हम उनका हृदय से सम्मान करते है और आवाह्न करते है कि वे सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, राजनैतिक शुचिता तथा भारत के पुर्नोत्थान के लिए अधिक से अधिक संख्या में पार्टी से जुड़ें। राष्ट्रीय सनातन पार्टी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करती हैं।

स्वतंत्र व पारदर्शी राजनीति के लिए राष्ट्रीय सनातन पार्टी के साथ जुड़कर कार्य करें।

सनातन अधिकार आंदोलन

5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान

बहुसंख्यक सनातन हिन्दू समाज के संवैधानिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रव्यापी जनसमर्थन अभियान

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक माध्यमों से अपनी बात रखने, जनमत तैयार करने तथा सरकार और संसद के समक्ष नीतिगत एवं विधायी परिवर्तन के प्रस्ताव रखने का अधिकार देता है।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी, भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत एक राजनीतिक दल होने के नाते, बहुसंख्यक सनातन हिन्दू समाज के संवैधानिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े विषयों पर जनसमर्थन प्राप्त करने हेतु "सनातन अधिकार आंदोलन" के अंतर्गत 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान प्रारम्भ कर रही है।

हम, भारत के हस्ताक्षरकर्ता नागरिक, भारत सरकार एवं भारत की संसद से लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित मांगों पर आवश्यक संवैधानिक संशोधन, विधायी सुधार एवं नीतिगत निर्णय करने का आग्रह करते हैं—

हमारी प्रमुख मांगें

1. संविधान के भाग–1, अनुच्छेद–1 में उपबंध 'क' जोड़ा जाए, जिसमें यह प्रावधान किया जाए कि—

"भारत एक सनातन राष्ट्र है और भारत का राज्य इस राष्ट्र की सेवा के लिए गठित सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है।"

2. संविधान के अनुच्छेद–25 में उपबंध (3) जोड़ा जाए, जिसके अनुसार भारत के बहुसंख्यक सनातन समुदाय को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो तथा राज्य बहुसंख्यक समाज की अनुमति के बिना उसके धार्मिक आचरणों पर प्रतिबंध न लगा सके। धार्मिक संस्थाओं के नियम बनाने का अधिकार संबंधित संस्थाओं को ही प्राप्त हो तथा असहमति रखने वाले लोगों को पृथक धार्मिक संस्थाएँ स्थापित करने की स्वतंत्रता हो।

3. संविधान के अनुच्छेद–28 एवं 30 में संशोधन कर बहुसंख्यक सनातन समाज को भी धार्मिक शिक्षा का समान अधिकार प्रदान किया जाए।

4. हिन्दू मंदिरों के प्रशासन एवं संपत्ति से संबंधित वर्तमान कानूनों की समीक्षा कर एक समान मंदिर अधिनियम बनाया जाए, जिसके अंतर्गत मंदिरों का प्रबंधन हिन्दू समाज को सौंपा जाए तथा उनकी आय एवं संपत्ति का उपयोग हिन्दू समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में किया जाए। प्रत्येक बड़े मंदिर के चढ़ावे से गुरुकुल, अन्नक्षेत्र, गौशाला संचालन की व्यवस्था हो तथा निर्धन सनातनी हिन्दू परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

5. पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को निरस्त कर सनातन धर्म स्थल पुनर्स्थापना अधिनियम बनाया जाए, जिससे ऐतिहासिक रूप से विवादित महत्वपूर्ण हिन्दू मंदिरों के संबंध में वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जा सके।

6. वक्फ अधिनियम को पूरी तरह समाप्त कर वक्फ संपत्तियों को सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया जाए तथा उनका उपयोग शासकीय एवं सार्वजनिक हित में किया जाए।

7. ईसाई चर्चों को दी गई दीर्घकालीन (99 वर्ष) लीजों की समीक्षा की जाए तथा संविधान एवं प्रचलित कानूनों की व्यापक समीक्षा कर सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल प्रावधानों को निरस्त अथवा संशोधित किया जाए।

8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को पूर्णतः निरस्त किया जाए। बौद्ध, जैन एवं सिख भारतीय मत हैं तथा ईसाई एवं मुसलमान मतावलंबियों की जनसंख्या 2% से अधिक होने के कारण इनके अल्पसंख्यक विशेषाधिकारों को समाप्त करने हेतु आवश्यक संवैधानिक एवं विधायी संशोधन किए जाएँ तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का विधिक ढांचा समाप्त किया जाए।

9. अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाओं में यदि धार्मिक आधार पर पात्रता निर्धारित है, तो उसकी समीक्षा कर समानता के सिद्धांत के अनुरूप बहुसंख्यक हिन्दू समाज को भी समान अवसर प्रदान किए जाएँ।

10. जातिवाद को असंवैधानिक घोषित किया जाए, जाति प्रमाणपत्र व्यवस्था समाप्त की जाए तथा शासकीय महत्व के सभी अभिलेखों में जाति के उल्लेख पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवश्यक संवैधानिक एवं विधायी प्रावधान किए जाएँ।

यदि आप मानते हैं कि इन विषयों पर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार विचार कर आवश्यक संवैधानिक संशोधन, विधायी सुधार एवं नीतिगत निर्णय किए जाएँ, तो आज ही अपना समर्थन दर्ज करें।

आपका एक हस्ताक्षर परिवर्तन की दिशा में एक कदम है।

यदि 5 करोड़ सनातनी एकजुट होकर अपनी बात रखेंगे, तो यह हिन्दू समाज की एक सशक्त लोकतांत्रिक आवाज बनेगी।

आस्था से अधिकार तक — एकजुट हो हिन्दू समाज

सनातन अधिकार आनोलन के महान कार्य को पूरा करने के लिए हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। कृपया राष्ट्रीय सनातन पार्टी से जुड़ें- हमारी शक्ति बनें।

हमारी महत्वपूर्ण कार्ययोजनाएं

राजनीतिक व्यवस्था

वर्तमान की धोखाधड़ी वाली राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिये राष्ट्रीय सनातन पार्टी सत्ता में आने के बाद चुनाव सुधार (Electroral Reform) का कार्य करेगी।

राजनेताओं द्वारा चुनाव में किए गए वादे, चाहे वे घोषणा पत्र के रूप में हों अथवा मंच पर जनता को अपने

पक्ष में लाने के लिए गए हों, वह एक कानूनी अभिलेख(Legal Documents) होगा, यदि नेता सत्ता में आने के बाद या जीतने के बाद जनता से किए वादे पूरे नहीं करता है तो उसे उसका कारण कोर्ट को बताना होगा और यदि कारण संतोषजनक न हो तो उस नेता के आगे चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगे, क्योंकि यह मतदाताओं को धोखा देना माना जाएगा, नेता ने जनता से झूठ बोलकर वोट लिया।

सभी राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग को आरटीआई (RTI) के दायरे में लाया जायेगा।

अनुदान देने वाले व्यक्ति और कंपनियों की पहचान सार्वजनिक की जाएगी ताकि चुनाव में पारदर्शिता आए। जनता को पता चले कि किस पार्टी को किस व्यक्ति, संस्थान या कंपनी से अनुदान (चंदा) मिल रहा है।

विदेशी अनुदान पर पूरी तरह से रोक लगेगी, जो अभी विदेश की भारत में स्थित सहायक कंपनियों के माध्यम से सभी पार्टियां प्राप्त कर रही हैं। इससे देश की राजनीति और सरकार में विदेश और अंतरराष्ट्रीय लॉबिस्टों का हस्तक्षेप समाप्त होगा।

भाजपा सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करके कंपनियों व कारपोरेट सेक्टर को यह छूट दी गयी है कि वह अपने वार्षिक लाभ-हानि खाते में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले अनुदान को छुपा सकते है। इससे राजनीतिक दल और सरकार ऐसी कंपनियों को देश व जनता की कीमत पर अनुचित लाभ प्रदान करती हैं। कंपनी अधिनियम में भाजपा सरकार द्वारा किए गये इस संशोधन को समाप्त किया जायेगा और कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी कंपनियों अपने वार्षिक लेखा-जोखा में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले अनुदान का विवरण अनिवार्य रूप से दे।

कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी वार्षिक पांच करोड़ से अधिक अनुदान किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दे सकते है। इससे चुनाव में बढ़ रहे अत्यधिक खर्च को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

स्त्री सशक्तिकरण के लिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढाई जाएगीं। राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं की राजनीति में कम से कम 33% भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी और इसके लिए राष्ट्रीय सनातन पार्टी ने अपने स्तर पर एक पहल अभी से शुरू कर दी है, पार्टी संगठन में विधानसभा कार्यकारिणी से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक कम से कम 33% महिलाओं को समायोजित किया जा रहा हैं।

शिक्षा व्यवस्था

किसी भी राष्ट्र की उन्नति में शिक्षा का महत्व सर्वाधिक होता हैं। पवित्र वेद शास्त्रों में विद्या की महिमा बताई गयी हैं, वे समस्त मानव जाती को शिक्षित, सुसंस्कृत व संगठित होने का आदेश देते हैं। राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान देगी।

मूल्यों पर आधारित संस्कारों के साथ भारतीय भाषाओं में सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनायी जायेगी। विज्ञान, गणित, तकनीकी, प्रबंधन, अभियन्त्रिकी, चिकित्सा व प्रशासकीय आदि सभी प्रकार की शिक्षा राष्ट्रभाषा, संस्कृत भाषा व अन्य प्रादेशिक भारतीय भाषाओं में ही दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

ऐसा होने पर एक गरीब मजदूर व किसान के पुत्र-पुत्री भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, आई.ए.एस, आई.पी.एस. व अधिकारी बन सकेगे तथा देश के सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकेगा।

भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में भारतीयों के स्वाभिमान व आत्मसम्मान को नष्ट करने के लिए तथा देश के बच्चों का नैतिक व चारित्रिक पतन करने हेतु हम भारतीयों के मन मस्तिष्क में बचपन से ही अपने पूर्वजों के ज्ञान, जीवन व चरित्र के बारे में एक षड़यन्त्र के तहत झूठी, मनगढंत, निराधार व अपमानजनक बातें पढ़ाई जा रही है, जिससे हम भारतीय हर बात में विदेशी लोगों के विचार, दर्शन और संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानकर स्वयं से व अपने पूर्वजों से घृणा करने लगते है।

यह घृणित व अपमानजनक षड़यन्त्र हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक कलंक की तरह जारी है। राष्ट्रीय सनातन पार्टी इस षड़यन्त्र को पूरी तरह समाप्त कराकर सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण कराएगी।

तथ्यों के आलोक में भारतीय इतिहास का पुर्नलेखन कराया जाएगा।

विवादस्पद प्राचीन भवनों की जाँच कराकर उनके निर्माण का श्रेय उनके वास्तविक निर्माताओं को देगे, जिससे भारत का सुप्त स्वाभिमान जाग्रत होगा।

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में विदेशी सत्ताओं का साथ देकर देश के साथ गद्दारी करने वाले नेताओं की संदेहस्पद भूमिका की निश्पक्ष जांच करायी जाएगी तथा उनके नाम पर संचालित योजनाओं का नाम परिवर्तन किया जाएगा।

किसी भी तरह की शिक्षण संस्था में, वो संस्था सरकारी हो अथवा निजी, सभी बच्चों को प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क दिया जाना अनिवार्य किया जाएगा।

भारत में विज्ञान व इतिहास की कालजयी परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए तथा कालगणना के लिए श्रीकृष्ण संवत को अपनाकर राष्ट्रीय पंचांग के रूप में लागू किया जायेगा।

सनातन वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा तथा अनुच्छेद 30 को संशोधित कर हिंदूओं को भी अपने स्वायत्त शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार मिलेगा।

सरकारी नौकरी में वैदिक शिक्षा की स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया जायेगा।

भारतीय मनीषियों द्वारा किये गए शोध और खोज को उन्हीं के नाम से पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा। उनका श्रेय उन विदेशियों को नहीं दिया जाएगा जिन्होंने उनके कार्यों को चुरा कर, उसे अपने नाम से प्रकाशित किया हो।

मातृ भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता, उच्च शिक्षा की पढ़ाई भी मातृ भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 10 तक संस्कृत अनिवार्य होगी।

केन्द्रिय परीक्षाओं में अंग्रेजी प्रश्नपत्र की अनिवार्यता समाप्त करके संस्कृत, हिन्दी व क्षेत्रिय भाषाओं को वैकल्पिक आधार प्रदान किया जायेगा।

संस्कृत भाषा के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति बनायी जाएगी, उसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जायेगा तथा संस्कृत माध्यम से संस्कृत शिक्षा दी जाएगी।

प्रत्येक राज्य में एक- एक केन्द्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

संस्कृत में व्यवसायिक, रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जायेगा एवं संस्कृत में रोजगार के अधिक अवसरों को उपलब्ध कराया जाएगा।

दूरदर्शन संस्कृत की स्थापना की जाएगी।

विद्यालयों में चरित्र निर्माण शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा व सैन्य शिक्षा अनिवार्य की जायेगी।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी का संकल्प है कि हमें भारत को संसार का सर्वाधिक सशक्त और समृद्ध देश बनाना है, इसलिए हम भारत की शिक्षा नीति को व्यवहारिक बनाएगे।

बच्चों को बचपन से ही चरित्र निर्माण के लिए योग, स्वास्थ्य, ललित कला, संगीत, स्वदेशी भोजन, ऋतुचर्या, औषधि, गौसेवा, खगोल, ज्योतिष, रसायन आदि प्राचीन भारतीय विद्याओं का क्रियात्मक व व्यवहारिक प्रशिक्षण विद्यालयों में दिया जाना अनिवार्य करेगे, साथ ही अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संस्कृतभाषा, संस्कृति एवं संस्कारों के प्रति आत्म गौरव का भाव जागृत करेंगे एवं भारत के गौरवशाली स्वर्णिम अतीत के बारे में बच्चों को बताकर उनमें स्वाभिमान का भाव भरेंगे।

हम विद्यालयों/महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा लागू करेगे जिससे की छात्र/छात्रा पढ़ लिखकर अपना कोई व्यवसाय कर सके। विद्यार्थियों को इतना सक्षम बनाया जाएगा कि वे विद्यालयों/महाविद्यालयों में ही अपने पैरों पर खड़े हो सके। साथ ही विद्यालयों/महाविद्यालयों में सैन्य शिक्षा को अनिवार्य किया जायेगा।

भारत की शिक्षा नीति गुरूकुल पद्धति पर होगी तथा गुरूकुल की सभी अच्छी बातों का समावेश भारत की शिक्षा नीति में होगा जिससे की आने वाली पीढ़ी का बौद्धिक विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण भी होगा।

NCERT की सभी पुस्तकों का पुनः निरीक्षण तथा भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन किया जायेगा।

संविधान में संशोधन कर एक देश-एक शिक्षा बोर्ड बनाया जायेगा। पूरे देश में एक-समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी तथा मदरसा शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त किया जायेगा।

कोचिंग शिक्षा प्रणाली को हतोत्साहित किया जायेगा।

लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर शिक्षक भर्ती आयोग का गठन किया जायेगा। शिक्षकों के सम्मान को राष्ट्र-निर्माता के रूप में स्थापित किया जायेगा।

शिक्षा में ठेका प्रणाली बंद होगी और सभी शिक्षकों को स्थायी नौकरी मिलेगी। सरकारी स्कूलों और सरकारी विश्व विद्यालयों के शिक्षा और आधारभूत संरचना के स्तर में विश्व-स्तर का बदलाव करेंगे।

मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में डोनेशन को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा तथा उनकी पढ़ाई को मातृभाषा में प्रोत्साहित किया जायेगा।

भारतीय मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा उस पर शोध करने के लिए एक अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारतीय कला और साहित्य को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मानविकी (Arts) की पढ़ाई में शोध को विश्व स्तरीय बनाया जायेगा तथा मानविकी से मौलिक विषय पर PhD करने वालों को केवल एक परीक्षा के आधार पर सिविल सेवा में सीधे भर्ती किया जायेगा।

प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) को रोकने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। सरकारी संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को दूसरे देशों में स्थानांतरित होने से पहले कम से कम 3 वर्षों तक अपने देश में ही सेवा देनी होगी।

भारत वर्ष सनातन एवं वैदिक सभ्यता का मूल इतिहास NCERT कोर्स में शामिल किया जाएगा।

ओलंपिक एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय खेलों में अमेरिका, रूस, चीन, और जापान स्तर की सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

BCCI एवं अन्य खेल संघों में बड़े पद कर केवल उस खेल को खेलने और समझने वाले खिलाड़ी ही प्रशासनिक पदों के लिए पात्रता रखेंगे।

राजनेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के लोगों का खेल से जुड़े विभिन्न संगठनों में हस्ताक्षेप बंद कराया जायेगा।

ग्राम स्तर तक खेल-कूद की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राएं भी एशियाड, ओलिंपिक आदि प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो सकें।

स्वास्थ्य व्यवस्था

हम मानते है कि स्वास्थ्य सेवाएँ सस्ती व हानि रहित तथा देश के सभी नागरिकों की पहुँच में होनी चाहिए। देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सभी नागरिकों का समान अधिकार होना चाहिए तथा मूलभूत स्वास्थ सेवा प्रत्येक नागरिक तक नि:शुल्क पहुँचाना सरकार का दायित्व होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करेगी ताकि प्रत्येक नागरिक को समान स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

आयुर्वेद, योग, पंचगव्य, प्राकृतिक, सिद्ध व यूनानी आदि सम्पूर्ण भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर अनुसन्धान को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर विश्व-स्तरीय बनाया जायेगा। एलोपैथी के साथ सभी वैकल्पिक चिकित्सा पद्दतियों का एकीकरण किया जायेगा।

आयुर्वेदि चिकित्सा पद्धति (और उसमे भी गौ आधारित औषधि) के शोध में अधिक बजट दिया जायेगा।

आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित किया जायेगा।

निजी अस्पताल में 25% गरीबों का निशुल्क इलाज की अनिवार्यता को सख्ती से लागू किया जायेगा।

सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पताल के समकक्ष खड़ा किया जायेगा।

आयुष्मान भारत में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जायेगा। आयुष्मान भारत में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जायेगा तथा भारत के प्रत्येक परिवार को इससे जोड़ा जायेगा।

हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक चिकित्सालय खोल कर वहां स्थायी मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।

MBBS/MD डॉक्टरों के लिए गांव में पांच वर्ष सेवा देना अनिवार्य होगा।

डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाये जाएंगे।

कानून व्यवस्था

भारत में चल रहे ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के समस्त नियमों-कानूनों को राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार अमान्य घोषित करेगी, साथ ही सत्ता-हस्तांतरण के बाद की सरकारों द्वारा बनाए गए वो क़ानून जो राष्ट्रहित में नहीं है, राष्ट्र के नागरिको की एकता को प्रभावित करते हैं, उन्हें भी बदला जायेगा।

भ्रष्टाचार, बलात्कार, दहेजहत्या, गौहत्या, आतंकवाद व मिलावट करने वालों के विरूद्ध मृत्युदण्ड का कानून बनाकर समस्त भारतीयों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए देश में फास्टट्रेक कोर्ट बनवाकर एक से तीन माह में तुरन्त न्याय की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि अपराधियों को तुरन्त दण्ड मिल सके और इन

भ्रष्टाचार व बलात्कार आदि करने वालों के मृत्यदण्ड के कानून को राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से मुक्त कराया जाएगा।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी देश के नागरिकों के लिए एक दंड संहिता बनाएगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, अर्थ व कृषि व्यवस्था का पूर्ण भारतीयकरण व स्वदेशीकरण किया जाएगा।

कोर्ट में जूरी व्यवस्था लागू की जायेगी।

साम्प्रदायिक आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों को निरस्त कर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

वर्तमान भारतीय व्यवस्था जाति व धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकों में भेदभाव करती हैं, यह व्यवस्था धर्म व जाति के आधार पर किसी नागरिक को सामान्य, तो किसी नागरिक को विशेषाधिकार देती हैं। इस वैधानिक भेदभाव के चलते देश में जातीय व साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा हैं, जो राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिए घातक हैं, और कालांतर में गृहयुद्ध का कारण भी बन सकता हैं।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार बनने पर राष्ट्रहित में बहुविधानों के स्थान पर संविधान लागू किया जायेगा तथा उन सभी व्यवस्थाओं को बदला जाएगा जो किसी भी तरह से भारतीय नागरिकों में भेदभाव करती हैं। समान नागरिक संहिता लागू करके देश की जनता को समानता का अधिकार दिया जायेगा।

सनातन धर्म को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जायेगा।

मंदिर एक्ट बनाकर सनातनी मंदिरों की संपत्ति को सुरक्षित किया जायेगा। हिन्दू मठ मंदिरों की संपत्ति केवल सनातन हित में उपयोग की जा सकेंगी। सनातन हिन्दू मंदिरों का धन केवल हिन्दू समाज के उत्थान व सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार – प्रसार में ही खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सभी बडे मंदिरों में देवालय के साथ ही गुरुकुल, अन्नक्षेत्र, जलाशय, चिकित्सालय व गौशाला संचालन की व्यवस्था की जायेगी। मंदिरों के चढ़ावे से गरीब सनातनी हिन्दुओं को आर्थिक सहायता दी जायेगी, जिससे धर्मांतरण रुकेगा, सनातन धर्म सशक्त बनेगा।

वक्फ-संपत्ति व शत्रु-संपत्ति का सरकारीकरण किया जायेगा।

शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को पुन: चालू किया जायेगा।

जातिवाद को असंवैधानिक घोषित किया जायेगा, सरकारी महत्व के अभिलेख, विद्यार्थी पंजीकरण, मूल निवास, जॉब पंजीकरण आदि परिपत्रों में जाति लिखने को प्रतिबंधित किया जायेगा।

सभी मत/रिलीजन के भारतीय नागरिकों के लिए अधिकतम तीन संतान उत्पन्न करने का कठोर जनसंख्या

कानून बनाना, इस कानून की अवमानना करने वाले को सभी सरकारी सुविधाओं व वोट के अधिकार से वंचित किया जायेगा।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार बनने पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की तरह ही सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जायेगा।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक सौ रूपये से अधिक बड़े नोटों का प्रचलन बंद किया जायेगा।

भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जायेगा तथा भ्रष्टाचारियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जायेगा।

विदेशी फंड से संचलित होने वाली देश-विरोध गतिविधियां अथवा सभी धार्मिक कृत्यों पर पूर्णता अंकुश लगाएंगे।

सत्ता में आने के 3 साल के भीतर बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं तथा बाकी सभी अवैध घुसपैठियों को निर्वासित कर उन्हें उनके मूल देश में भेजा जायेगा।

पूरे देश में NRC लागू करेंगे।

कश्मीर से निकाले गए हिन्दुओं को सुरक्षा के साथ पुनस्थापित किया जायेगा और हिन्दुओं के नरसंहार को अधिकारी रूप से नरसंहार घोषित कर यूएन कन्वेन्शन ऑन क्राइम्स अगेंस्ट जीनोसाइड के तहत नरसंहारियों (जिहादियों) को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत दंडित किया जायेगा।

वक्फ एक्ट, Places of Worship Act को निरस्त किया जायेगा।

सच्चर कमेटी के क्रियान्वयन को तत्काल निरस्त किया जायेगा।

हिन्दू धर्म से घृणा सिखाने वाली नवबौद्धों की चौबीस प्रतिज्ञाओं को प्रतिबंधित किया जायेगा तथा इन प्रतिज्ञाओं का पठन-पाठन, प्रकाशन व प्रचार-प्रसार को कठोर दंडनीय अपराध बनाया जायेगा।

धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगेगी तथा इसके लिए कठोर कानून लाये जाएंगे।

माता-पिता की अनुमति के बिना कन्याओं को जबरन अथवा लालच दे कर अथवा झूठ बोल कर किया जा रहा अंतर-धार्मिक विवाह तथा विवाहेतर सम्बन्ध के विरुद्ध कठोर कानून लाया जायेगा।

प्रेम विवाह की स्थिति में लड़की व लड़के के माता-पिता दोनों की सहमती अथवा दोनों पक्षों में से एक-एक, माता अथवा पिता की सहमती होना आवश्यक हैं, ऐसा न होने की स्थिति में प्रेम विवाह अमान्य घोषित किया जायेगा।

लव जिहाद पर कठोरतम दंड का प्रावधान किया जायेगा।

विवाह विवाद में न्याय-प्रक्रिया में जाने से पहले मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया जायेगा।

ऐसी समितियाँ बनायी जाएंगी जिनमें सम्मानित वरिष्ठ नागरिक, उच्च सेवानिवृत्त लोग, तथा समाज के अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। वैवाहिक विवाद के सभी मामले अदालतों में जाने से पहले इन समितियों के पास जाएंगे।

प्राचीन भारतीय न्याय प्रणाली खाप पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जायेगी।

सनातन विवाह संस्कार पर समलैंगिकता के आक्रमण को हतोत्साहित किया जाएगा और समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जायेगी।

परिवारों को संयुक्त बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

मृत्यु उपरांत श्राद्ध के लिए तेरह दिनों के अवकाश को सभी संस्थानों में अनिवार्य किया जायेगा।

घरेलू हिंसा के कानूनों में महिलाओं के समान ही पुरुषों को भी जोड़ कर इनको लिंग के प्रति तटस्थ (Gender-Neutral) बनाया जायेगा।

सरकार, न्यायालय अथवा एक्टिविस्टों द्वार परिवार तोड़ने के लिए लाये गए सेक्शन-69 जैसे प्रावधानों को समाप्त किया जायेगा।

चल-अचल पैतृक संपत्ति में पुरुषों के अधिकार के समान ही महिलाओं को मायका या ससुराल में से केवल एक जगह ही अधिकार दिया जायेगा।

महिला आयोग की आधार पर ही राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन किया जायेगा।

फिल्म, कला, OTT अथवा स्कूली पुस्तकों से व्यभिचार को बढ़ावा देने वाली तथा परिवार को तोड़ने वाली सामग्री हटाई जायेगी। ऐसी सामग्री डालने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

परिवार को तोड़ने वाले सभी कानूनों की समीक्षा की जायेगी।

पुलिस सुधार किये जाएंगे। पुलिस का सशक्तिकरण तथा आधुनिकीकरण किया जायेगा।

भीड़ के द्वारा किये गए संगठित और नियोजित पथराव को राष्ट्रद्रोह माना जाएगा तथा इसके लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान होगा।

भीड़ के द्वारा सरकारी अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर उस नुकसान की वसूली उनकी चल अचल सम्पति को जब्त करके किया जायेगा। इसके लिए केंद्रीयकृत कानून लाया जायेगा।

अरबी साम्राज्यवाद की मजहबी हिंसा के शिकार लोगों को आत्मरक्षा के लिए सस्ते लाइसेंस दिए जायेगे। इसके लिए लाइसेंस के अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन किये जाएंगे।

CISF की तर्ज पर "धार्मिक संपदा सुरक्षा सेना" का गठन किया जायेगा जो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

सभी मुख्य मंदिरों के 10 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस के प्रयोग पर रोक लगेगी।

सनातन मूल्यों के प्रचार प्रसार को विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में जोड़ा जायेगा।

संसार के सभी सनातन धर्मियों के लिए भारत को उनका प्राकृतिक राष्ट्र घोषित कर उनके लिए नागरिकता का मार्ग खोला जायेगा।

भारत के बाहर बसे भारतीयों को नस्लवाद, गुटबाजी, भेदभाव आदि से हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

भारत देश केवल उन्हीं देशों की सहायता करेगा जो सनातन मूल्यों को सम्मान देते है।

नेपाल के हिन्दू राष्ट्र बनने का समर्थन किया जायेगा।

भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए मध्य पूर्व, अफ्रीका, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और लैटिन अमेरिका में सहयोगियों को बढ़ाएंगे।

यूरोप के General Data Protection Regulation (GDPR) की तर्ज पर देश के लोगों के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कानून लाये जायेंगे। किसी भी कंपनी के द्वारा भारतीयों के डाटा को रखने तथा इस्तेमाल करने के तरीके में आमूल- चूल परिवर्तन किया जायेगा। लोगों को अपने डाटा को सुरक्षित करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त किया जायेगा।

लोगों के व्यक्तिगत डाटा का दुरुपयोग कर के लक्षित विज्ञापन (Targeted advertising) चलाने को रोका जायेगा। कोई भी कंपनी, किसी के भी प्राइवेट डाटा को बिना उसकी अनुमति के उपयोग नहीं कर सकेगी।

PPP मॉडल पर भारत के स्वदेशी डाटा सेंटर खड़े किए जाएंगे जो भौतिक रूप से भी देश की सीमा में ही होंगे।

सरकार, फौज तथा उनसे जुड़े सभी कर्मचारियों का संवेदनशील डाटा और उनका व्यक्तिगत डाटा केवल देश के भीतर के डाटा सेंटरों में ही रखा जाएगा जिसे देखने का अधिकार किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं होगा।

सरकार तथा उससे जुड़े संस्थानों के सभी कर्मचारी किसी भी विदेशी प्लेटफार्म (जैसे Gmail, WhatsApp

आदि) की जगह केवल स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को ही उपयोग करेंगे।

सर्च इंजन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उत्पन्न परिणामों में देश तथा सनातन के विरोध में दिखाए जा रहे झूठे रिजल्ट के विरुद्ध कानून लाया जायेगा।

कानून बनाकर आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए प्रमुख 40000 सनातनी हिंदू मंदिरों का पुनर्नोद्धार किया जायेगा।

वैज्ञानिक आधार पर बने श्रीकृष्ण सम्वत वैदिक पंचांग को सरकार का ऑफिसिपल कैलेंडर बनाया जायेगा।

प्रमुख और बड़े सनातनी त्योहारों पर छुट्टी अनिवार्य की जाएगी।

भारतीय गौवंश की हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाकर ऐसा करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान लाया जायेगा।

भारत में हलाल सर्टिफिकेशन को पूर्ण रूप से बंद किया जायेगा तथा इसका उलंघन करने वालों पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

मदरसों को दिया जाने वाला सरकारी अनुदान पूर्णतः समाप्त किया जायेगा।

भारत में किसी भी स्थान या परियोजना का नाम विदेशी आक्रांताओं अथवा देश के गद्दारों के नाम पर नहीं होगा। एक केंद्रीय कानून ला कर ऐसी सभी स्थानों का नाम एक बार में ही उनके मौलिक नाम के आधार पर बदल दिया जाएगा।

तीर्थ क्षेत्रों में पंडों द्वारा सुरक्षित रखे गए सभी सनातनी पूर्वजों के रिकॉर्ड को मान्यता प्रदान करते हुए डिजिटाइज़ कर उसका ऑफिसियल डाटा सेंटर बनाया जायेगा जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे पंठों को सरकारी अनुदान दिया जायेगा।

अपने पूर्वजों के मूल सनातन धर्म में घर वापसी करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जायेगा।

सभी मंदिरों एवं तीर्थ क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री तथा प्रयोग पर रोक लगेगी।

सिनेमा, OTT तथा टीवी पर ऐसे कंटेंट बनाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो अपने कंटेंट के माध्यम से बच्चों में अच्छे संस्कारों को बढ़ावा देते हैं। सनातन मूल्यों, भारतीय सेना, स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय ऋषियों, आदि की गलत छवि पेश करने वाले सभी कंटेंट को पूर्णतः हटाया जायेगा।

न्यू वर्ल्ड आर्डर (जहाँ बच्चों में समलैंगिकता तथा लिंग परिवर्तन जैसी चीजों को प्रोत्साहित किया जाता हो) को प्रोत्साहन देने वाले कंटेंट पर प्रतिबंध लगाया जायेगा।

हिन्दू साधु-संतों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर उनपर झूठे केस करके फसाने वाले तथा उनको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना देने वालों के खिलाफ कठोरतम दण्ड का प्रावधान लाया जायेगा।

न्यू वर्ल्ड आर्डर के हर अजेंडे (WTO, WHO, One Religion, Depopulation, बच्चों में समलैंगिकता तथा लिंग परिवर्तन जैसी चीजों को प्रोत्साहित करना, आदि) से भारतीय नागरिकों के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा।

फिल्म सेंसर बोर्ड को भारतीय मूल्यों के अनुरूप ढाला जाएगा।

अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तरलोचन सिंह के अनुसार, 58 जातियों और 14 जनजातियों में मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। वहीं, वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले के अनुसार, 80 फीसदी मुस्लिम ओबीसी में आरक्षण का लाभ ले रहे हैं।

SC/ST तथा OBC में आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिम, ईसाई तथा नवबौद्धों को तत्काल आरक्षण से बहार निकाला जाएगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति में मुस्लिम-ईसाई आरक्षण का रास्ता ढूंढने के लिए भाजपा सरकार द्वारा बनाए गये डॉ. बालाकृष्णन कमेटी को तत्काल रद्द किया जाएगा।

SC/ST तथा OBC वर्ग के पहली से बारहवीं कक्षा तक लगातार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा।

बिना जांच के SC/ST ACT में गिरफ्तारी पर रोक लगेगी। गलत आरोप पाए जाने पर आरोप लगाने वाले पर जुर्माने का प्रावधान होगा तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार केस में न्यायालय का अंतिम निर्णय आने के उपरान्त ही पीड़ित को मुआवजा दिया जायेगा।

सनातन संस्कृति एवं सभ्यता को हानि पहुंचाने वाले अनुच्छेद, कानून तथा धाराओं की समीक्षा कर, उन्हें निरस्त किया जायेगा।

अर्थ व्यवस्था

अर्थ व्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। यदि किसी देश की सम्पन्नता का आंकलन करना हो तो वहाँ के व्यापारियों को देखकर वहाँ की सम्पन्नता का आंकलन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार बनने पर स्वदेशी अर्थ व्यवस्था की ऐसी नीतियाँ बनायी जाएगी जिससे किसान व व्यापारी सम्पन्न बने, रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न हो तथा रुपये का अवमूल्यन रुके, रूपये को

डालर व पौंड के बराबर लाया जा सकें, जो लगभग 15 अगस्त 1947 के समय में था।

लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा तथा चीन की तरह ही अपने देश के युवाओं को व्यापार करने के लिए एकल खिड़की तंत्र प्रणाली (One Window system) विकसित करेगे ताकि लोगों को व्यापार करने के लिए आवश्यक पूँजी और संसाधन सरलता से उपलब्ध हो सकें।

स्वदेशी अर्थव्यवस्था को अपनाकर अर्थात दूसरे देशों में निर्यात बढाकर एवं आयात घटाकर प्रतिवर्ष कम से कम 20 से 30 लाख करोड़ रूपये विदेशी मुद्रा भारत में लाकर राष्ट्र को समृद्ध व वैभवशाली बनाएगे।

गौवंश आधारित अर्थव्यवस्था का तंत्र विकसित करके गौमूत्र व गौबर से दवाइयां, खाद व भवन निर्माण सामग्री निर्मित की जाएगी तथा गौबर गैस का उपयोग घर की रसोई में खाना पकाने से लेकर वाहनों को चलाने तक में किया जाएगा, जिससे पेट्रोल, डीजल व गैस के लिए विदेशी निर्भरता तो कम होगी, साथ ही देश की मुद्रा देश में रहेगी, जिससे भारत के किसान भी सम्पन्न हो जाएगे।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार भारत की कर (Tax) नीति में बड़ा बदलाव करके उसे कम करेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को घाटे से निकालकर लाभ में लाने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) पर काम किया जाएगा ताकि शीघ्र से शीघ्र भारत को कर मुक्त राष्ट्र बनाया जा सके।

भारत के अपने स्वदेशी विश्वस्तरीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विकसित करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे लोगों का डाटा सुरक्षित होने के साथ-साथ देश में बड़े स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। इससे आईटी सेक्टर में हो रहा प्रतिभा पलायन भी रुकेगा।

AWS, गूगल क्लाउड, आदि के आधार पर भारत का अपना स्वदेशी पब्लिक क्लाउड बनाया जायेगा।

इस क्षेत्र में एक करोड़ से अधिक नौकरियों सृजित की जाएगी।

देश भर में सहारा के सभी निवेशकों के डूबे हुए पूरे पैसे रिफंड कराये जाएंगे।

LIC बीमा धारकों की आर्थिक सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

शारदा चिट फंड आदि जैसी लुभावनी स्कीम पर रोक लगा कर छोटे निवेशकों को लुटने से बचाया जायेगा।

बोफोर्स घोटाला, PM केयर फंड घोटाला, कॉफिन घोटाला, 2G घोटाला, आदि सभी घोटाले जिनके कारण सत्ता बदली और जिन्हें नई सरकार द्वारा सत्ता में आने पर दबा दिया गया, ऐसे सभी घोटालों की समय-बद्ध जांच कर उसमे सत्ता-पक्ष विपक्ष, नौकरशाही, तथा मीडिया की जिम्मेदारी तय की जायेगी।

रियल एस्टेट के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट में जिन लोगों का पैसा फसा हुआ है, उन सभी लोगों को उनका घर या पैसा एक साल के भीतर दिलाया जायेगा।

कृषि व्यवस्था

हमारे देश की 60% जनता आज भी कृषि पर निर्भर है, राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार किसान आयोग का पुनर्गठन करेगी जो कृषि के औद्योगीकरण, खाद्य-प्रसंस्करण व फसलों के मूल्यांकन की एक स्वस्थ व नई नीति बनाएगा, जिससे खेती घाटे का सौदा न रहें, गाँवों से पलायन रूके, साथ ही किसान आत्महत्या के लिए मजबूर न हो।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी कृषि लागत और मूल्य आयोग(Commission for Agricultural Costs and Prices)की भी समीक्षा करेगी तथा उसमें आवश्यक संशोधन करेगी ताकि कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सके व किसानों को उनकी लागत का कम से कम दो गुना मूल्य मिल सके।

जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहन नीति बनायी जाएगी। जैविक कृषि से विष रहित अन्न, शाक, सब्जियां व फलादि उपलब्ध होंगे जो हमारे देश के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की रक्षा व राष्ट्र की रक्षा के लिए अति आवश्यक है।

हम जल संरक्षण के परम्परागत व प्राकृतिक उपायों को अपनाकर जल की एक - एक बूंद को धरती के गर्भ में उतारने का पूर्ण प्रयास करेंगे तथा बड़े बांधों की योजनाओं को निरस्त कर पर्यावरण के अनुकूल छोटे – छोटे बांधों की योजना पर कार्य किया जाएगा। सिंचाई हेतु नई नहरों का निर्माण कराया जायेगा।

सौर-ऊर्जा, पवन-ऊर्जा आदि वैकल्पिक ऊर्जा के संयंत्रों का तंत्र विकसित किया जायेगा।

माँ गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी आदि सभी पवित्र नदियों में सीवर के गंदे पानी और औद्योगिक अपशिष्टों को डालने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जायेगा।

राष्ट्रीय मार्गों पर भारतीय मूल के उपयोगी वृक्षों (पीपल, बरगद, आम, जामुन, आदि) को बड़ी मात्रा में लगाया जायेगा।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार बनने पर केन्द्रीय गौवंश मंत्रालय गठित करके स्वदेशी गौवंश को प्रोत्साहन की नीति बनाई जाएगी। केन्द्रीय योजना बनाकर जिला स्तर पर एक एक लाख गौवंश की क्षमता वाली गौशालाएँ बनवाकर, उनमें बेसहारा गाय, बैल व सांडों को रखकर गौवंश आधारित उद्योगों की शुरूआत की जाएगी।

गैस, बिजली, खाद, औषधि, भवन सामग्री आदि गौवंश से उत्पन्न कर विदेशी मुद्रा बचायी जाएगी, तथा गाँवों में गौवंश आधारित संयंत्र स्थापित करने के लिए गौवंश पालक किसानों को सबसिडी देने का प्रावधान किया जाएगा, जिससे भारतीय किसान आत्मनिर्भर बनेगे।

गौचर भूमि को मुक्त करा कर गांव स्तर पर पंचायती खर्चे पर चारागाहों की व्यवस्था की जायेगी जिससे पशु-धन पर हो रहा किसान का खर्चा कम होगा (दिन में पशु गौचर भूमि में खुला हुआ रहेगा) और पशु-धन स्वस्थ रहेगा। पशु-धन को संभालने के लिए किसान को कम मेहनत करनी होगी।

ग्राम-स्तर पर गोधन केंद्र खोले जाएंगे जहाँ सरकार ग्रामीणों से गोबर, गौमूत्र तथा जैविक रसोई एवं कृषि अपशिष्ट खरीदेगी। बैलों से खेती करने वाले किसानों को विशेष सुविधाएँ प्रदान की जायेगी।

पूरे देश के किसानों के लिए सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जायेगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव तय किये जाएंगे।

मौसमी प्राकृतिक मार से हुए फसल के नुकसान का मुआवजा 90 दिनों के भीतर देने की व्यवस्था की जायेगी।

जैविक खाद बनाने के लिए पंचायत और ब्लाक स्तर की सहकारिता संगठनों को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान रखा जायेगा। इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी।

सरकार द्वारा भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे कर अपाहिज बनाने की व्यवस्था समाप्त की जायेगी। उन लोगों को हमारी सरकार द्वार गांव के स्तर पर ही कुटीर उद्योग स्थापित करके दिया जायेगा। उनके उत्पाद को सरकार सीधे खरीदेगी। इससे वे याचक की जगह एक लघु उद्यमी के रूप में अपने साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे पायेगे।

नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां एवं खाद बनाने वाली कंपनियों पर कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया जायेगा।

गांव में सहकारिता आधारित उपक्रमों को खड़ा किया जायेगा।

गाँव में कृषि के साथ गैर कृषि आधारित आर्थिक इकाइयों को भी खड़ा किया जायेगा।

हाइब्रिड बीज समाप्त कर पारंपरिक तरीके से बीज संरक्षण किया जायेगा।

फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।

डब्ल्यूटीओ (WTO) की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर भारतीय किसानों के हितों के संरक्षण को सर्वोपरि रखा जायेगा।

सैन्य व्यवस्था

राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार विद्यालयी समय से ही देश के छात्र-छात्राओं को सैन्य शिक्षा दिया जाना अनिवार्य करेगी, जिससे देश में सैनिकों की कमी नहीं रहेगी। सेना में अग्निवीरों को स्थाई नियुक्ति दी जायेगी।

भारत के सैनिक और अर्धसैनिक बलों, तथा पुलिस के जवानों को अत्याधुनिक शस्त्र और ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि हमारी सेना और हमारे जवान हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम हों।

देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जायेगी। जिससे कारगिल या गलवान क्षेत्र में हुई घुसपैठ जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सकें। साथ ही विदेशी नागरिक अवैध रुप से प्रवेश न कर सकें। सीमाओं की सुरक्षा के लिये सीमान्त क्षेत्रों का पूर्ण विकास, आधुनिक अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सेना तथा आधुनिक पुलिस बल सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

पुलिस और सेना में पेंशन बहाली (एक रैंक एक पेंशन) की जायेगी।

सेना के जवानों के लिए आजीवन वेतन योजना लाई जाएगी जिससे कि यदि कोई जवान बलिदान भी होता है तो उसके परिजनों को उसकी सेवा निर्वत्ति की आयु तक वेतन और अन्य सुविधाएँ मिलती रहेगी जिससे कि किसी भी सुरक्षाकर्मी के परिवार को व्यक्ति के ना रहने पर कम से कम असुविधाओं का सामना ना करना पड़े।

भारतीय सेना के परंपरागत ढांचे को अक्षुण्ण रखा जायेगा।

सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों को उचित सम्मान दिया जायेगा।

यदि आप राष्ट्रहित और जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय सनातन पार्टी से जुड़कर कार्य करें।

आशा है की आप राष्ट्रीय सनातन पार्टी के सदस्य बनकर संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, राजनीतिक शुचिता व सनातन को संवैधानिक संरक्षण दिलाने के इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालेगे, जिससे राष्ट्र धर्म को बल मिलेगा और भारत अपना पुनर्वैभव प्राप्त करेगा।

www.rashtriyasanatanparty.org

संपर्क विवरण

मोबाइल: 9410073474, 8535004500

ई-मेल: **contact@rashtriyasanatanparty.org**

सादर धन्यवाद।

जय सनातन, विजय सनातन।